The Himachal Pradesh Prevention of Malpractices at University, Board and other Specified Examinations Act, 1984

Act 19 of 1984

Keyword(s):
Examination, University

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

(4) If any person fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(5) If any person released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

16. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, and no suit, prosecution of other legal proceeding shall lie against any person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

17. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Forest Based Essential Commodities Ordiance, 1984 (2 of 1984), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act, had come into force on 27th June, 1985.

हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम, 1984

(1984 अधिनियम संख्यांक 19)[1]

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1· संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2· परिभाषाएं ।

3· प्रश्न-पत्र बनाने वालों के कर्तव्य और उल्लंघन के लिए दण्ड ।

4· ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य जिन्हें प्रश्न-पत्रों का मुद्रण आदि सौंपा गया है, और उल्लंघन के लिए दण्ड ।

5· ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य जिन्हें प्रश्न-पत्रों की अभिरक्षा सौंपी गई है, और उल्लंघन के लिए दण्ड ।

6· परीक्षा होने से पूर्व किसी प्रश्न-पत्र के प्रदाय या प्रकाशन का प्रतिषेध ।

7· परीक्षा में नकल करने और प्रतिरूपण का प्रतिषेध ।

8· अधीक्षक या वीक्षक पर हमला आदि ।

1· उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश असाधारण, तारीख 12 अप्रैल, 1984, पृष्ठ 700 देखें ।

9· परीक्षा के संचालन और परिणामों की घोषणा के कार्य की मनाही के लिए दण्ड ।

10· अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड ।

11· अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

12· अपराधों का संक्षेपतः विचारण ।

हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम, 1984 ।

(30 जुलाई, 1984 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश असाधारण में तारीख 18 अगस्त, 1984 को पृष्ठ 1469--1471 पर प्रकाशित किया गया ।)

हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की परीक्षाओं में अनाचार के निवारण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1· **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम, 1984 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2· **परिभाषाएं**.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,--

(क) "बोर्ड" से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968,(1968 का 14) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए स्थापित स्कूल शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परीक्षा" से किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा ली गई या लिए जाने के लिए प्रस्तावित कोई परीक्षा अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा ली गई या लिये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी अन्य परीक्षा भी है जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की गई या की जाय; और

(ग) "विश्वविद्यालय" से हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

3. प्रश्न-पत्र बनाने वालों के कर्तव्य और उल्लंघन के लिए दण्ड--(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी परीक्षा में प्रश्न-पत्र बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है, इस निमित्त उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गये लिखित अनुदेशों के अनुसार के सिवाए, किसी व्यक्ति को अपने द्वारा बनाये गए प्रश्न-पत्र या उसकी प्रति का प्रदाय नहीं करेगा या नहीं करायेगा या ऐसे प्रश्न-पत्र की अन्तर्वस्तु की सूचना नहीं देगा या किसी भी रीति से उसका प्रचार नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

4. ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य जिन्हें प्रश्न-पत्रों का मुद्रण आदि सौंपा गया है और उल्लंघन के लिए दण्ड.--(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी परीक्षा के प्रयोजनार्थ बनाए गए किसी प्रश्न-पत्र के मुद्रण, चक्रलेखन, टंकण या अन्यथा प्रतियाँ बनाने का कार्य सौंपा गया है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे यह कार्य सौंपा है, दिए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार के सिवाए, किसी व्यक्ति को उसकी प्रति का प्रदाय नहीं करेगा या नहीं कराएगा या उसकी अन्तर्वस्तु की सूचना नहीं देगा या किसी भी रीति से उसका प्रचार नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

5. ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य जिन्हें प्रश्न-पत्रों की अभिरक्षा सौंपी गई है और उल्लंघन के लिए दण्ड.--(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी परीक्षा के प्रयोजनार्थ बनाए गए किसी प्रश्न-पत्र की अभिरक्षा सौंपी गई है या वह अन्यथा उसके कब्जे में है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे उसकी अभिरक्षा सौंपी है या कब्जा दिया है उसे दिए गए लिखित अनुदेश के अनुसार के सिवाए, किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रति का प्रदाय या वितरण नहीं करेगा या नहीं करायेगा या उसकी अन्तर्वस्तु की सूचना नहीं देगा या किसी भी रीति से उसका प्रचार नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

6. परीक्षा होने से पूर्व किसी प्रश्न-पत्र के प्रदाय या प्रकाशन का प्रतिषेध.--जो कोई विश्वविद्यालय, बोर्ड या परीक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार के सिवाए, अपने कब्जे में, किसी

परीक्षा के लिए बनाया गया या बनाया गया तात्पर्यित कोई प्रश्न-पत्र रखेगा और परीक्षा होने से पूर्व चाहे किसी प्रतिफल के लिए या अन्यथा, किसी व्यक्ति को, उसकी प्रति का प्रदाय करेगा या कराएगा या प्रदाय के लिए प्रस्थापना करेगा या उसकी विषयवस्तु की सूचना देगा या सूचना देने की प्रस्थापना करेगा, या किसी भी रीति में उसका प्रचार करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

7• **परीक्षा में नकल करने और प्रतिरूपण का प्रतिषेध**;-- जो कोई वीक्षक या परीक्षा के संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, परीक्षा भवन में या इसकी पांच सौ मीटर की परिधि के भीतर, परीक्षा के लिए बनाए गए प्रश्न-पत्र के उत्तरों को किसी पुस्तक, टिप्पणी या अन्य परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका से नकल करते हुए या परीक्षा में किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देते हुए या किसी अन्य अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाएगा, वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

8• **अधीक्षक या वीक्षक पर हमला आदि**.-- (1) परीक्षा केन्द्र का प्रत्येक अधीक्षक और प्रत्येक वीक्षक परीक्षा या परीक्षाओं के दौरान और ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने से एक मास पूर्व और ठीक छः मास पश्चात् तक की अवधि के लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि के दौरान किसी परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या वीक्षक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) की धारा 186 के अधीन दण्डनीय लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से पहुंचाई गई बाधा समझी जाएगी ।

9• **परीक्षा के संचालन और परिणामों की घोषणा के कार्य की मनाही के लिए दण्ड**.--जो कोई, जिसे परीक्षा के संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन परीक्षा परिणाम को सारणीबद्ध या प्रकाशित करने या परीक्षा से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य या उसके परिणामों के प्रकाशन का कार्य सौंपा गया है, उसे सौंपे गए किसी कृत्य को करने से इन्कार करेगा, वह, दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, किन्तु जो एक मास से कम नहीं होगी या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो दो हजार रूपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक मास से कम अवधि के कारावास का या दो हजार रूपये से कम जुर्माने का, दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा ।

10. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड.-- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

11. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अ   तीय होंगे :

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा ।

12. अपराधों का संक्षिप्त विचारण.--इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी भी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और जहां तक हो सके ऐसे विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 तक के (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित है) उपबन्ध लागू होंगे ।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh, Vishv-Vidyalaya, Board ya Anya Vinirdisht Parikshaon mein Anachar Ka Nivaran Adhiniyam, 1984 (1984 ka Adhiniyam Sankhyank 19) as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF MALPRACTICES AT UNIVERSITY, BOARD OR OTHER SPECIFIED EXAMINATIONS ACT, 1984

(ACT No. 19 of 1984)[1]

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Duties of paper setters and punishment for contravention.
4. Duties of persons entrusted with printing etc. of question papers and punishment for contravention.
5. Duties of persons entrusted with custody of question papers and punishment for contravention.
6. Prohibition of supply or publication of any question paper before examination is held.
7. Prohibition of copying and impersonating at examinations.
8. Assault etc. on Superintendent or Invigilator.
9. Punishment for refusal to work for the cor declarations of results of an examination.

1. For Statement of Objects and Reasons see R.H.P. Extra., dated 12 P. 704.

10. Punishment for abetment of offences.

11. Offences to be cognizable and non-bailable.

12. Offences to be tried summarily.

(Recived the assent of the President of India on the 30th July, 1984 and was published in R.H.P.(Extra.) dated the 18th August, 1984 at page 1472-1474)

An Act to provide for preventing malpractices at Examinations of any University or the Board or any other specified authority in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India, as follows:--

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prevention of Malpractices at University, Board or other Specified Examinations Act, 1984.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,--

(a) "Board" menas the Board of School Education for the State of Himachal Pradesh established under the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (14 of 1968);

(b) "examination" means any examination held or proposed to be held by any University or the Board and includes such other examination held or proposed to be held by such other authority as may be specified in this behalf, from time to time, by the State Government by notification in the Official Gazette; and

(c) "University" means any University established by law in the State of Himachal Pradesh.

3. **Duties of paper setters and punishment for contravention.**—(1) Any person who is appointed as a paper setter at any examination shall not supply or cause to be supplied the question paper drawn by him or a copy thereof or communicate the contents of such paper to any person or give publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions given to him in writing by his appointing authority in this behalf.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

4. **Duties of persons entrusted with printing etc. of question papers and punishment for contravention.**— (1) Any person who is

entrusted with the work of printing, cyclostyling, typing or otherwise producing copies of any question paper set for the purposes of any examination shall not supply, or cause to be supplied, a copy thereof or communicate the contents thereof to any person or give publicity thereto in any manner, except in accordance with the instruction given to him in writing by the authority which entrusted the work to him.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

5. **Duties of persons entrusted with custody of question papers and punishment for contravention.**— (1) Any person who is entrusted with the custody, or is otherwise in possession, of any question paper set for the purposes of any examination shall not supply or distribute or cause to be supplied or distributed any copy thereof or communicate the contents thereof to any person or give publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions given to him in writing by the authority which entrusted the custody or gave possession thereof to him.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

6. **Prohibition of supply or publication of any question paper before examination is held.**--Whoever has in his possession any question paper set or purported to be set for any examination and supplies or causes to be supplied or offers to supply a copy thereof, or communicates or offers to communicate the contents thereof, to any person, whether for any consideration or otherwise, or gives publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions issued in writing by an authorised officer of the University, Board or other authority concerned with the examination, at any time before the examination is held, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

7. **Prohibition of copying and impersonating at examinations.**—Whoever is found in or within the periphery of 500 metres of an examination hall by the invigilator or any other person appointed to supervise the conduct of the examination, copying answers to the question paper set at a examination, from any book, notes or answer paper of other candidate, or appearing at the examination for any other candidate or using any other unfair means, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

8. **Assault etc. on Superintendent or Invigilator.**— (1) Every Superintendent and every Invigilator of an examination centre shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860) during the course of an examination or examinations and for a period of one month prior to the commencement of and of six months immediately following such examination or examinations.

(2) An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent or an Invigilator of an examination centre during the period mentioned in sub-section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions, punishable under section 186 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

9. Punishment for refusal to work for the conduct and declaration of rusults of an examination.—Whoever, being entrusted with the conduct, supervision, evaluation of answer sheets, tabulation or publication of results of an examination, or any other work connected with the examination or the publication of its result, refuses to discharge any function assigned to him, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months but shall not be less than one month. or with fine which may extned to five thosuand rupees but shall not be less than two thousand rupees, or with both :

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one month or a fine of less than two thousand rupees.

10. Punishment for abetment of offences.—Whoever abets any offence punishable under this Act shall be punishable with the punishment provided for such an offence.

11. Offences to be cognizable and non-bailable.— Notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable offences and shall be non-bailable:

Provided that any person who has not attained the age of 18 years, when arrested shall be released on bail.

12. Offences to be tried summarily.—All offences under the Act shall be tried in a summary way by any Judicial Magistrate of the First Class and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, as far as may be, apply to such trials.

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983

[1984 का अधिनियम संख्यांक 3][1]

धाराओं का क्रम

अध्याय-1

प्रारंभिक

धाराएँ :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 24 दिसम्बर, 1983, पृष्ठ 1288 देखें ।